



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 25 जुलाई, 1992/3 श्रावण, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

आदेश

शिमला-2, 1 जुलाई, 1992

संख्या: एग्र०-एफ०-7 (2)/86-III.—भारत सरकार, कृषि मन्त्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग), नई दिल्ली द्वारा राजपत्र (असाधारण), भाग-2, खण्ड 3, उप खण्ड-II द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1-2/92-उवरक-विधि, दिनांक 10-2-1992 को हिमाचल प्रदेश के राजपत्र (असाधारण) में आम जनता की सूचना तथा उसके हित में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (कृषि)।

सं० 1-2/92-उर्वरक-विधि

भारत सरकार

कृषि मन्त्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली:

तारीख 10 फरवरी, 1992.

अधिसूचना

का० आ० 125 (ई).—केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 3 के उपखण्ड (1) के अनुसरण में, भारत सरकार के कृषि मन्त्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 516 (अ), तारीख 14 अगस्त, 1991 का, जो तुरन्त प्रभावी होगा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, एन्हाइडस अमोनिया से सम्बन्धित मद संख्या 22 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

1	2
"23 अमोनियम नाइट्रेट फास्केट (23-23-0)	3800
24 जस्तायुक्त यूरिया	4220"

हस्ताक्षरित/-,
(शांता शीला नायर),
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

आवास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 जून, 1992

संख्या: लोक निर्माण (के एच ए) 28(26)/85.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश माधारण खण्ड अधिनियम, 1968 की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए इस सरकार की अधिसूचना संख्या लोक निर्माण (के एच ए) 28(26)/85, दिनांक 2-11-1991 को निम्नलिखित विस्तार तक संशोधित करते हैं अर्थात् :—

संशोधन

“क्रम संख्या 1, पर आए शब्दों “डिप्टी कमिशनर, कुल्लू” के स्थान पर “डिवीजनल कमिशनर, मण्डी” शब्द रखे जायेंगे।”

आदेश द्वारा,

आर० एस० धर,
आयुक्त एवं सचिव (आवास)।

[Authoritative English text of this Government notification No. Lok Nirman (kha) 28 (26)/85, dated 2-11-91 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

HOUSING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th June, 1992

No. Lok-Nirman (kha) 28 (26)/85.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 67 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977) read with section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to amend this Government notification No. Lok Nirman (kha) 28(26)/85, dated 2-11-1991 to the following extent namely :—

AMENDMENT

“For the words “Deputy Commissioner, Kullu” appearing at Sl. No. 1, the words “Divisional Commissioner, Mandi” shall be substituted”.

By order,

R. S. DHAR,
Commissioner-cum-Secretary(Housing).

सामान्य प्रशासन विभाग
(एफ-शाखा)

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 1992

संख्या: सा० प्र० वि० (एफ) 1 (ए) 4-4/92.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, लम्बित स्वतन्त्रता सेनानी घोषित करने सम्बन्धी आवेदन-पत्रों की जांच पड़ताल हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक स्क्रूनिंग कमेटी के

गठन के लिए सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

- | | |
|---|----------------------|
| 1. श्री भास्करा नन्द, भूतपूर्व विधायक, गांव/डाकघर बसनापुर, तह0 सुन्नी, जिला शिमला । | सचालक
(कन्वीनर) । |
| 2. महाशय तीर्थ राम, गांधी सेवा आश्रम, अग्रिल, तह0 अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0) । | सदस्य |
| 3. श्री दौलत राम सांख्यान, भूतपूर्व मन्त्री, गांव पंचायतन, डाकखाना जुखाला, तह0 सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) । | सदस्य |
| 4. श्री कृष्ण चन्द बैद्य, स्वतन्त्रता सेनानी, मकान नं0 91/1, वार्ड नं0 11, टारना रोड मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) । | सदस्य |
| 5. श्री ज्ञान चन्द अलमस्त, स्वतन्त्रता सेनानी, गांव/डाकघर जबालामुखी, तह0 देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) । | सदस्य |
| 6. अवसर सचिव (सामान्य प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार । | सदस्य-सचिव |

कमेटी के कार्य :

यह स्क्रीनिंग कमेटी सामान्य प्रशासन विभाग(एफ-शाखा) में लम्बित स्वतन्त्रता सेनानी घोषित करने सम्बन्धी आवेदन-पत्रों की छानबीन करेगी और छानबीन करने के उपरान्त यह स्क्रीनिंग कमेटी अपनी सम्पूर्ण सिफारिश सहित हिमाचल प्रदेश सरकार सामान्य प्रशासन (एफ-शाखा) को प्रस्तुत करेगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त स्क्रीनिंग कमेटी हर मास में एक बैठक अवश्य आयोजित करेगी और जहां तक सम्भव हो उपरोक्त लम्बित आवेदन-पत्रों को तीन-चार मास के भीतर निपटाया जाये।

गैर-सरकारी सदस्यों की संलग्न परिशिष्ट के नियमानुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

इस मामले पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति अनौपचारिक संख्या: 527-फिन(सी)ए(9)1/89-पार्ट, दिनांक 9-6-92 द्वारा प्रदान कर रखी है।

आदेश द्वारा,

पी0 एस0 नेगी,
आयुक्त एवं सचिव ।

अनुबन्ध

यात्रा भत्ता

(क) रेल द्वारा यात्रा :

गैर-सरकारी सदस्य को प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारी के समान माना जाएगा और वस्तुतः प्रयोग की गई वास्तु विधि के धर्म के वानानुकूलित जगह के अतिरिक्त वास्तविक यात्रा भाड़े का हकदार होगा।

(ख) सड़क द्वारा यात्रा :

यात्रा की दशा में सड़क मील दूरी, केन्द्र जो रेल के साथ सम्बन्ध न ही, के बीच में, गैर-सरकारी सदस्य निम्न सड़क मील दूरी के हकदार होंगे :—

(I) यदि यात्रा वास्तविक भाड़ा देकर की गई हो,
जैसे लोक बस द्वारा एकल सीट/स्थान

(II) मोटर साईकिल/स्कूटर द्वारा यात्रा की दशा में ।

(III) पूरी टैक्सी या अपनी कार द्वारा यात्रा की दशा में ।

(क) पहाड़ी क्षेत्र के लिए । 80 पैसे प्रति कि० मी० ।

(ख) समतल क्षेत्र के लिए । 60 पैसे प्रति कि० मी० ।

(क) पहाड़ी क्षेत्र के लिए । 2.50 पैसे प्रति कि० मी० ।

(ख) समतल क्षेत्र के लिए । 2.00 रुपये प्रति कि० मी० ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त उन्हें विभाग से प्रारम्भ होने वाले स्थायी निवास स्थान से उनकी कुल अनुपस्थिति के लिए और स्थायी निवास स्थान पर पहुंचने की समाप्ति के साथ सरकारी कर्मचारी को लागू निबन्धन और शर्तों और निम्न पैरा 5 की शर्तों के अध्याधीन दैनिक भत्ता मिलेगा ।

2. दैनिक भत्ते :

(क) गैर-सरकारी सदस्य बैठक के प्रत्येक दिन के लिए अपने-अपने परिक्षेत्र और प्रथम श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को लागू होने वाले निबन्धन और शर्तों के अध्याधीन उच्च दर पर दैनिक भत्ता मिलेगा ।

(ख) बैठक के दिनों के लिए दैनिक भत्ते के अतिरिक्त सदस्य दौरे पर और निम्न बोर्ड/समिति के कार्यों से सम्बन्ध वाहरी स्टेशन पर विराम के लिए दैनिक भत्ते का हकदार भी होगा :—

(क) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक न हो

—

(ख) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 6 घण्टे से अधिक परन्तु 12 घण्टे से अधिक न-हो ।

70 प्रतिशत

(ग) यदि मुख्यालय से अनुपस्थिति 12 घण्टे से अधिक है

पूर्ण

3-अ. प्रवहण भत्ता :

गैर-सरकारी सदस्य जो उस स्थान, जहां बोर्ड/समिति की बैठक धारित हुई है का निवासी हो, को यहां उपदर्शित मान पर यात्रा और दैनिक भत्ता जो अधिकतम 10/- रुपये प्रति दिन हो लेने का हकदार नहीं होगा। इससे पहले कि दावा वस्तुतः सन्दर्भ किया जाये, नियन्त्रक अधिकारी दावे को सत्यापित करेगा और ऐसा ब्यौरा जिसे आवश्यक समझे अभिप्राप्त करके कि वास्तविक व्यय दावे की राशि से कम नहीं था अपना समाधान करेगा । यदि इस ब्यौरे से उनका समाधान नहीं होता तो वह अपने विवेक पर प्रवहण भत्ते के सड़क मील दूरी तब सीमित कर सकेगा । यदि ऐसा सदस्य अपनी कार का प्रयोग करता है तो उसे प्रथम श्रेणी के अधिकारी को मील दूरी भत्ता अनुदेय दर से अधिकतम 10/- रुपये प्रति दिन के अनुसार दिया जायेगा ।

4. सदस्य को यात्रा और दैनिक भत्ता उनके द्वारा इस भाव का प्रमाण-पत्र पेश करने पर दिया जायेगा कि उसने उनी यात्रा के लिए सरकार के किसी अन्य स्त्रोत से यात्रा का दैनिक भत्ता नहीं लिया है।

5. गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक से सम्बन्ध की गई वास्तविक यात्रा के लिए और उसके स्थायी निवास स्थान जो पहले से ही नामित किया गया हो या भत्ते का पात्र होगा। यदि कोई सदस्य बोर्ड/समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए अपने स्थायी निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थानों की यात्रा करें या बैठक समाप्त होने के पश्चात् उसके स्थायी निवास स्थान से भिन्न अन्य स्थान या ऐसे अन्य स्थान और बैठक का स्थान, जिसकी दूरी कम है, को वापिस आता है।

6. गैर-सरकारी सदस्य को यात्रा भत्ते के खाते में अतिसंदाय की दशा में हिमाचल प्रदेश खजाना नियम के नियम 4.17 और 6.1 के उपबन्ध तथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

7. गैर-सरकारी सदस्य जो विधान सभा का सदस्य हो, ने बोर्ड/समिति के काम से सम्बन्ध यात्रा की हो समय-समय पर संशोधित विधान सभा अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्त सदस्यों के वेतन और भत्ते के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

8. सदस्य उनके समनुदेशन से सम्बन्ध दैनिक भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा जब विधान सभा या विधान सभा समिति जिस पर सदस्य सत्र में सेवा करते हैं जैसे विधान सभा सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम के अधीन वे अपने दैनिक भत्ते ले रहे हैं, हालांकि यदि वे प्रमाणित करें कि उन्हें सदन के सत्र या विधान सभा समिति के हाजिर होने से निवारित किया गया हो और विधान सभा से कोई दैनिक भत्ता नहीं लिया है, वे विनिर्दिष्ट दर से दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

9. सदस्य जिसे विधान सभा से निरहित किया गया हो प्रवहण भत्ते के अन्तर्गत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता भी नहीं लेगा।

समाज एवं महिला कल्याण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 जुलाई, 1992

संख्या: कल्याण-क(4)-13/79-II.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 सितम्बर, 1990 के क्रम में हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम अधिनियम, 1979 (1979 का 20वां अधिनियम) की धारा 87 की उप-धारा (1) व (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री चेतन राम नेगी, निवासी चगांव, जिला किन्नौर को हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम में गैर-सरकारी निदेशक मनोनीत करते हैं।

2. राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-9-1990 के क्रम संख्या 14 पर दर्शाए गए जीवन मनेजर, पंजाब नेशनल बैंक के स्थान पर उप-अंचल प्रबन्धक (सहायक महा-प्रबन्धक) का मनोनीत करने में भी अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आर० के० आनन्द,
वित्तियुक्त एवं सचिव (कल्याण)।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 6 जुलाई, 1992

पृष्ठांकन संख्या: पंच-के० जी० आर०(एम) 17/91-1123-27.—क्योंकि ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड लम्बागांव ने अपनी पंचायत की बैठक दिनांक 26-3-1992 के प्रस्ताव संख्या 3 के अन्तर्गत पारित किया है कि उनकी पंचायत के वार्ड नं० 2 में चयनित पंच श्री प्रमोद सिंह का दिनांक 21-3-1992 को देहान्त हो चुका है, जिसकी पुष्टि खण्ड विकास अधिकारी ने की है।

अतः मैं, के० जे० वी० वी० सुब्राह्मण्यम, अतिरिक्त उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, श्री प्रमोद सिंह, पंच, वार्ड नं० 2, ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड लम्बागांव की मृत्यु होने के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली, 1971 के नियम 19(आ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल उक्त पंच क पद को रिक्त घोषित करता हूँ।

के० जे० वी० वी० सुब्राह्मण्यम,
अतिरिक्त उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर स्थित रिकांग-पिअ्रो

कार्यालय आदेश

रिकांग-पिअ्रो, 18 जून, 1992

संख्या: कनर-158/61-8-477-86.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 10(2) तथा हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 19(बी०) में विहित शक्तियों के अन्तर्गत, मैं, दीपक सानन, उपायुक्त, जिला किन्नौर निम्नलिखित पदाधिकारियों के त्याग-पत्र इस आदेश के जारी होने की दिनांक से स्वीकृत करता हूँ तथा पंचायत में इनके स्थान को रिक्त घोषित करता हूँ :—

क्र० सं०	नाम पदाधिकारी	विवरण
1	श्री मोती ज्ञालछन नेगी, ग्राम पंचायत कानम, विकास खण्ड पूह।	प्रधान, ग्राम पंचायत कानम।
2.	श्री डबड नमजल, ग्राम पंचायत लिप्पा, विकास खण्ड पूह।	पंच वार्ड नं० 1, ग्राम पंचायत लिप्पा।

दीपक सानन,
उपायुक्त,
जिला किन्नौर।

